श्री बलरामजी दास टण्डन

माननीय राज्यपाल

छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

छत्तीसगढ़ विधानसभा का अधिवेशन

रायपुर, 2 मार्च, 2015

माननीय सदस्यगण, मेरी यह कामना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का, वर्ष 2015 में आयोजित यह प्रथम सत्र, जनता की खुशहाली के नए मार्ग प्रशस्त करे। आप सबके सहयोग से प्रदेश को विकास की नई दिशा मिले, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

2. लोकतंत्र की मजबूती के लिए समय पर निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य में विधानसभा, लोकसभा, नगरीय-निकाय तथा त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों का दौर पूरा हो गया है। इस सदन के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले सरकारी अमले तथा मतदाताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ । निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ ।

3. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनेक लोकप्रिय लोक अभियानों की शुरूआत की है। मेरी सरकार ने इन कार्यक्रमों को समुचित प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। 'स्वच्छ भारत अभियान' को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ के गांवों में व्यापक जनजागरण किया जा रहा है। खुले में शौच की प्रवृत्ति पर रोकथाम के साथ शौचालयों के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। इस वर्ष गांवों में दो लाख 68 हजार शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्तर पर संचालित 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के साथ ही विशेष पहल करते हुए राज्य में 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' भी लागू की गई है।

4. 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के तहत प्रदेश में 99 प्रतिशत परिवारों के बैंक खाते खुलवाए जा चुके हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिलों को छोड़ कर, शेष सभी जिलों में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। पहले मात्र 16 लाख परिवारों के बैंक खाते थे, विगत 5 माह में 40 लाख परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं।

5. 'कुशल भारत' निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके कारण राज्य में देश की सबसे बड़ी कौशल विकास योजना, 'स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम' संचालित की जा रही है और छत्तीसगढ़ ने देश के कुल लक्ष्य का सातवां हिस्सा पूर्ण करने का दायित्व उठाया है। 'डिजिटल इंडिया' तथा 'मेक इन इंडिया' के आव्हान पर भी छत्तीसगढ़ ने बड़े कदम उठा लिए हैं। राज्य की नई 'सूचना प्रौद्योगिकी नीति' घोषित कर दी गई है।

6. मेरी सरकार के सतत प्रयासों से राज्य में कृषि फसलों के उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विगत चार वर्षों में तीसरी बार वर्ष 2013-14 के लिए छत्तीसगढ़ को केन्द्र शासन द्वारा 'कृषि कर्मण पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। 'कृषक समग्र विकास योजना' के तहत धान, गेहूं, कोदो-कुटकी व रागी फसलें लेने वाले किसानों को अनुदान का लाभ मिला है। दलहन और तिलहन बीज उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जैविक खेती मिशन योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है। कृषि यांत्रिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। ब्याज मुक्त कृृषि ऋण देने की अभिनव पहल का भरपूर लाभ किसानों को मिला है। 10 लाख से अधिक किसान भाई इस वर्ष 2600 करोड़ रूपए से अधिक का कृषि ऋण ले चुके हैं, जो कि अब तक का कीर्तिमान है। एक दशक में उद्यानिकी फसलों का

रकबा आठ गुना तथा उत्पादन चार गुना बढ़ गया है। उद्यानिकी फसलों के 20 प्रतिशत रकबे को 'ड्रिप एरिगेशन' के अंतर्गत लाया जा चुका है।

7. मछली बीज तथा मछली उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश का छठवां बड़ा राज्य बन गया है। विभिन्न जिलों में मत्स्य बाजार स्थापित किए जा रहे हैं। मछली पालकों के कल्याण व विकास हेतु 'मछुआ कल्याण बोर्ड' का गठन भी किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व देखते हुए मेरी सरकार 21 नए पशु औषधालय स्थापित कर रही है। 20 पशु औषधालयों का उन्नयन पशु चिकित्सालयों के रूप में किया जा रहा है। छह जिलों में पशु चिकित्सा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

8. मेरी सरकार पंडरिया, जिला कबीरधाम में प्रदेश का चौथा, 'लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना' स्थापित करने जा रही है। इससे गन्ना किसानों को फसल का अच्छा दाम और समृद्धि का रास्ता मिलेगा। 'राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग' तथा 'छŸााीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण' का गठन भी किया गया है। मेरी सरकार ने भूमि संबंधी दस्तावेजों की कम्प्यूटरजनित नकल देना शुरू कर दिया है। पटवारी अपने कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहें इसके लिए पटवारी कार्यालय सह आवास का निर्माण किया जा रहा है। 17 तहसील कार्यालयों के भवन भी बनाए जाएंगे।

9. मेरी सरकार त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि करने के लिए सभी 27 जिलों में 'जिला पंचायत संसाधन केन्द्र' तथा 36 विकासखण्डों में 'खण्ड पंचायत संसाधन केन्द्र' बनाए जा रहे हैं। 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के अंतर्गत 6,800 महिला स्व-सहायता समूहों को 68 करोड़ रूपए का ऋण तथा 6 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों को 10 करोड़ रूपए का 'रिवाल्विंग फण्ड' उपलब्ध कराया गया है। योजना में विस्तार हेतु 29 अतिरिक्त विकासखण्डों का चयन किया गया है।

10. मेरी सरकार ने 'मनरेगा' का अधिक लाभ राज्य के जरूरतमंद परिवारों को दिलाने हेतु दो वर्षों में 80 हजार परिवारों को 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया है। यह बड़े गौरव का विषय है कि 'मनरेगा' के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए इस वर्ष दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर जिलों तथा ग्राम पंचायत फरफौद को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। 'अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना' के तहत 10 लाख 67 हजार खेतिहर मजदूरों का पंजीयन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कराया जा चुका है। इस वर्ष बी.पी.एल. आवासहीन परिवारों के लिए लगभग 40 हजार इंदिरा आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 'मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना' के तहत वर्ष 2014-15 हेतु 250 करोड़ रूपए लागत के आठ हजार से अधिक निर्माण कार्यों की मंजूरी दी गई है।

11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक 23 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई की 5300 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, जिनसे लगभग 7800 बसाहटें जुड़ चुकी हैं। ग्रामीण सड़कों पर सुगम आवागमन के लिए 184 वृहद पुलों के निर्माण हेतु 385 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। नक्सल प्रभावित सात जिलों के 29 विकासखण्डों में सड़कों के निर्माण हेतु 575 करोड़ के प्ररस्ताव की सैद्धांतिक स्वीकृति केन्द्र से प्राप्त हुई है।

12. राज्य में अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनाने हेतु मेरी सरकार ने 'छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम' का गठन किया है जो नई रणनीति से नये संसाधन जुटाने तथा नयी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर बल देगा। विगत वर्ष विभिन्न मदों से लगभग पांच हजार किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। 150 से अधिक पुलों का काम हाथ में लिया गया जिसमें से 19 का काम पूरा हो गया है। 'एकीकृत पंजीयन प्रणाली' प्रारंभ की गई है, जिसके तहत 5300 से अधिक ठेकेदारों का पंजीयन किया जा चुका है।

13. मेरी सरकार ने 'हर घर शौचालय-हर घर नल' कार्यक्रम को मिशन मोड पर लागू करते हुए शहरी गरीब परिवारों को उनके घरों में तीन लाख 40 हजार से अधिक निजी शौचालय बनाने तथा सभी को 'भागीरथी नल-जल योजना' के तहत निःशुल्क नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। झुग्गियों और सार्वजनिक स्तरों पर 800 से अधिक सामुदायिक शौचालय भी बनाए जाएंगे। 141 नगरीय निकायों में 'मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन' से युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिये जाएंगे। 451 सिटी बसों के माध्यम से शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा का विस्तार किया जाएगा। शहरों के नियोजित विकास, गरीबी निवारण तथा मूलभूत सुविधाओं में विस्तार का अभियान सफलता के नए शिखरों तक पहुंचेगा।

14. मेरी सरकार ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण अभियान में 99 प्रतिशत सफलता हासिल कर ली है। स्कूल न जा सकने वाले शेष एक प्रतिशत से भी कम बच्चों की समस्या की पहचान की गई है। निःशक्त बच्चों की निःशक्तता का उपचार, घर में शिक्षा देने जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, सभी शालाओं में शिक्षक-शिक्षिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। एक लाख 38 हजार शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एडूसेट केन्द्रों में पी.एम.टी. एवं पी.ई.टी. के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित हैं। पूर्व माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में शत्-प्रतिशत पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संसदीय कार्य प्रणाली से छात्र-छात्राओं को अवगत कराने तथा जागरूकता लाने के लिए शालेय स्तर पर 'युवा संसद' कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जिलों से राज्य-स्तर तक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है।

15. मेरी सरकार ने प्रजातंत्र की जड़ें विद्यार्थी जीवन से मजबूत करने के लिए शासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराए हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। शैक्षणिक पदों के लिए लगभग एक हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। अनेक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय नैक से मूल्यांकन कराने की दिशा में आगे बढ़े हैं तथा एक विश्वविद्यालय तथा दो महाविद्यालयों को 'ए ग्रेड' की मान्यता मिली है।

16. मेरी सरकार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना का विकास कर रही है। राजनांदगांव के बाद रायपुर में भी सिंथेटिक सतह का हॉकी स्टेडियम तथा स्वीमिंग पूल लोकार्पित हो चुका है। 400 से अधिक खिलाड़ियों को इस वर्ष खेल पुरस्कार, राज्य खेल अलंकरण तथा नगद राशि

से पुरस्कृत किया गया। राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में पांच से छह एकड़ भूमि चिन्हित की जा रही है, जहां 'खेल परिसरों' का निर्माण किया जाएगा।

17. मेरी सरकार वन क्षेत्रों में जीवन की खुशियांे का विस्तार कर रही है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में उठाए गए कदमों के कारण उन्हे विगत वर्ष 171 करोड़ रूपए की मजदूरी दी गई है तथा 105 करोड़ रूपए का बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा 'जनश्री बीमा योजना', 'अटल समूह बीमा योजना', 'प्रोत्साहन योजना' का लाभ भी दिया जा रहा है। साल बीज संग्राहकों को 12 करोड़ रूपए से अधिक पारिश्रमिक मिला है। इसी तरह महुआ गुठली, लाख, चिरौंजी तथा इमली को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का कार्य राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। वनों के संरक्षण एवं विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए वनोपजों के उत्पादन के हिस्से के रूप में 24 करोड़ रूपए की राशि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को दी जाएगी। हिंसक वन्य प्राणियों से जन तथा पशु हानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। हाथियों और भालुओं द्वारा किए जाने वाले नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए 'गजराज' तथा 'जामवंत' परियोजना लागू की जा रही है।

18. मेरी सरकार के योजनाबद्ध प्रयासों के कारण एक दशक में ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुआ है। वर्ष 2003 की तुलना में 'ग्रामीण पेयजल प्रदाय योजना' में 28 गुना, 'ग्रामीण स्थल जल योजना' में पांच गुना, 'शहरी जल प्रदाय योजना' में आठ गुना, शालाओं में पेयजल प्रदाय में चार गुना तथा हैण्डपंप द्वारा पेयजल प्रदाय में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राज्य की 73 हजार से अधिक बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्त्रोत की व्यवस्था पूरी हो गई है।

19. मेरी सरकार ने शासन तथा प्रशासन की सुविधाएं निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की हैं, जिससे एक ओर युवाओं को रोजगार मिला, वहीं दूसरी ओर कार्यालयों में काम-काज सुचारू हुआ है। राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनरीक्षण से डिप्टी कलेक्टरों के 42 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। 1800 से अधिक पदों पर 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग' के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई है। प्रशासन को हर स्तर पर जवाबदेह बनाने के लिए 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011' के अंतर्गत 10 विभागों की अधिसूचित 31 सेवाएं जिला, तहसील, विकासखंड, नगर-निगम तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 'लोक सेवा केन्द्रों' के माध्यम से 'ऑन लाइन' उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। 'मोबाइल एप' के माध्यम से भी नागरिक सेवाओं तथा जानकारियों की प्रदायगी की जाएगी।

20. मेरी सरकार कला, संस्कृति, पुरातत्व, धरोहरों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निरंतर कदम उठा रही है। राजिम, तरीघाट तथा डमरू में पुरातात्विक अनुसंधान के लिए उत्खनन का कार्य कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना के विकास का लाभ मिलना शुरू हो गया है। विगत वर्ष सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश के दस प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है। प्रति वर्ष मनाए जाने वाले महोत्सवों की सूची में तातापानी तथा मैनपाट को भी जोड़ा गया है। राज्य में एडवेंचर, ईको, रूरल तथा रिलीजियस टूरिज्म की संभावनाओं के अनुरूप विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कराया जा रहा है।

21. मेरी सरकार ने जल संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है, जिसके कारण एक दशक में सिंचाई क्षमता लगभग दस प्रतिशत बढ़ी है। प्रदेश की तीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं में अरपा भैंसाझार (जिला बिलासपुर) के अंतर्गत 25 हजार हेक्टेयर, केलो (जिला रायगढ़ एवं जांजगीर चाम्पा) के अंतर्गत 23 हजार हेक्टेयर तथा मोहड़ (जिला बालोद एवं राजनांदगांव) 800 हेक्टेयर की क्षमता प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं को समयबद्ध तथा चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में कुल चार वृहद, चार मध्यम, 343 लघु सिंचाई परियोजनाएं और 325 एनीकट निर्माणाधीन हैं।

22. राज्य में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास से बड़े पैमाने पर कुशल रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसका लाभ युवाओं को देने के लिए मेरी सरकार ने कौशल विकास की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की है। कानून बनाकर कौशल प्रशिक्षण का अधिकार देने में छŸााीसगढ़ देश का अव्वल राज्य बना है। सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेजों में रहवासी प्रशिक्षण के साथ ही निजी क्षेत्र व उद्योगों की भागीदारी तय करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इससे हमारे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर तथा अग्रणी प्रशिक्षक दोनों मिलेंगे। इसी वर्ष आईआईटी तथा ट्रिपल आईटी के अलावा कोण्डागांव तथा सूरजपुर में पॉलीटेक्निक कॉलेज शुरू हो जाएंगे।

23. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ को देश के ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने की कार्य योजना सफलता पूर्वक संचालित की है, जिसके कारण विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां मिली हैं। राज्य में नए बिजलीघरों की स्थापना के क्रम में मड़वा की प्रथम इकाई क्रियाशील की जा चुकी है तथा दूसरी इकाई का निर्माण भी प्रगति पर है। पारेषण क्षमता को 4900 एम.वी.ए. से बढ़ाकर 7800 करने का लक्ष्य है। उपभोक्ता सेवा के लिए राज्यस्तरीय कॉल सेन्टर, ईमेल, नेट बैंकिंग से बिल भुगतान जैसी सुविधाएं दी गई हैं। परम्परागत बिजली से वंचित 95 विकासखंडों में सोलर टास्क लैम्प वितरित किए गए हैं। इन अंचलों के विद्यार्थियों को सोलर लैम्प दिए गए हैं। 'कृषक जीवन ज्योति योजना' के माध्यम से किसानों को निःशुल्क अथवा अत्यंत रियायती दर पर बिजली दी जा रही है। बिजली की मदद से कृषि फसलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मेरी सरकार ने शहरी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं संचालित की हैं ताकि बस्तियों और गलियों में रोशनी रहे।

24. मेरी सरकार ने राज्य में श्रम के सम्मान का ही नहीं बल्कि श्रमिकों को अधिकार और स्वावलम्बन देने का वातावरण भी बनाया है। पौने दो लाख ठेका श्रमिकों को दुर्घटनाआंे से बचाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। असंगठित क्षेत्र के लगभग 20 लाख श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हें दो दर्जन से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ऑन लाइन पंजीयन की व्यवस्था भी की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के तहत छह नए औषधालय शीघ्र शुरू करने की तैयारी है। भिलाई, कोरबा तथा रायपुर में अस्पताल स्थापित करने का भी लक्ष्य है।

25. मेरी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राशन दुकानों के कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। राशन कार्डों को आधार नंबर तथा बैंक खातों के साथ लिंक किया जाएगा, जिससे वास्तविक हितग्राहियों की पहचान सरलता से हो सके। खाद्यान्न की भण्डारण क्षमता

चार लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10 लाख मीट्रिक टन की गई है। इस वर्ष आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत पांच लाख 30 हजार मीट्रिक टन क्षमता के 72 गोदाम निर्माणाधीन हैं।

26. मेरी सरकार ने जनस्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण तथा आदिवासी बहुल अंचलों तक करने हेतु नए उपाय किए हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से बस्तर तथा सरगुजा संभाग में नर्सों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधायुक्त लेबर रूम तथा दस बिस्तरों का अस्पताल बनाया जा रहा है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना राजनांदगांव के पश्चात अब अम्बिकापुर में की जा रही है। बिलासपुर में नया शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी प्रारम्भ किया गया है।

27. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि शत-प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पूरक-पोषण आहार प्रदाय के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है। मेरी सरकार के विशेष प्रयासों से शत-प्रतिशत किशोरियों को पूरक पोषण आहार मिल रहा है। इसके लिए 17 'गैर सबला योजना' जिलों में राज्य निधि से व्यवस्था की गई है। 'चाइल्ड लाइन सेवा-1098' का विस्तार सात नए जिलों में किया जा रहा है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को बल मिले।

28. मेरी सरकार ने निःशक्तजनों के सम्मान और स्वावलम्बन हेतु सरकारी विभागों में पद चिन्हित किए हैं। राजनांदगांव में 'पुनर्वास केन्द्र' तथा श्रवणबाधित निःशक्तजनों के लिए महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत निःशक्तजनों को तीर्थाटन कराया गया। 'तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड' का गठन कर संबंधित व्यक्तियों के सम्मानजनक जीवनयापन की व्यवस्था की जा रही है।

29. मेरी सरकार ने राज्य में यातायात सेवा को सुगम बनाने के साथ आवश्यक दस्तावेज सुलभ कराने हेतु पारदर्शी व्यवस्था की है। यात्री वाहनों को परमिट, फिटनेस के आवेदन, कर भुगतान, विभिन्न प्रकार के लायसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन आदि से संबंधित सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा ऑन लाइन सेवाएं संचालित की गई हैं।

30. उत्कृष्ट और समृद्ध खनिज संसाधन हमारी बड़ी ताकत हैं। मेरी सरकार ने खनिजों के महत्व के अनुरूप इसके प्रबंधन के लिए समुचित दक्षता तथा पारदर्शिता लाने की रणनीति अपनाई है। वृहद कम्प्यूटराइजेशन योजना के तहत ई-जियोलॉजिकल मॉडलिंग, ऑनलाइन एप्लिकेशन एण्ड रिटर्न्स, बारकोड युक्त ई-ट्रांजिट पास, ई-पंजीयन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार भारत सरकार के 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश 2015' के तहत 'डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन' की स्थापना करेगी, जिसमें खनिपट्टा धारकों द्वारा रायल्टी की निर्धारित राशि जमा की जाएगी, जो खनन से प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्तियों के विकास में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खर्च की जाएगी। विगत वर्ष गौण खनिजों से प्राप्त 180 करोड़ रूपए से अधिक राशि, पंचायतों एवं नगरीय निकायों को आबंटित की गई है। मेरी सरकार द्वारा राज्य में खनिजों का लगातार अन्वेषण एवं विकास कर खनिजों के नए भण्डार आंकलित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य के राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

31. शहरों में नियोजित विकास तथा स्मार्ट सिटी के निर्माण हेतु मेरी सरकार ने 'नगर विकास योजना' तैयार करने पर बल दिया है। अब-तक 116 निवेश क्षेत्रों का गठन किया जा चुका है। 15 विकास योजनाएं तैयार हो चुकी है तथा 18 विकास योजनाएं तैयार करने का काम प्रगति पर है। देश की प्रथम स्मार्ट सिटी के रूप में 'नया रायपुर' के विकास की सर्वत्र सराहना हो रही है। 'नया रायपुर' में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बीआरटीएस पर क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। नॉन-मोटोराइज्ड ट्रांसपोर्ट हेतु पृथक से पाथवे व कॉरीडोर विकसित किया जा रहा है। 'नया रायपुर' में समाज के हर वर्ग की बसाहट को ध्यान में रखते हुए नई 'मुख्यमंत्री आवास योजना' के तहत 40 हजार प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें कमजोर आय वर्ग के लोगों को आकर्षक रियायतें व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

32. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के विकास हेतु मेरी सरकार ने शिक्षा को व्यापक परिवर्तन का माध्यम बनाया है और लीक से हटकर नए प्रयासों पर जोर दे रही है। 'मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना' के तहत 6 स्थानों पर आवासीय विद्यालय 'प्रयास' संचालित किए जा रहे हैं। 'वनबंधु कल्याण योजना', छात्रावासों में 'खाद्यान्न सुरक्षा योजना' तथा 'मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम', 13 नए छात्रावासों की स्थापना जैसे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। अनुसूचित जनजाति में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित रह गई जातियों को अनुसूचित जनजाति के समान अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

33. मेरी सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए जो सकारात्मक वातावरण बनाया है, उसके कारण अन्य राज्यों की तुलना में मंदी के विपरीत, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव केन्द्र शासन को मिला है। भारत सरकार की पहल 'मेक इन इंडिया' को सफल बनाने के लिए राज्य में नई औद्योगिक नीति 2014-19 को 'मेक इन छत्तीसगढ़' की सोच में ढाला गया है। प्रदेश में प्रदूषण मुक्त, कौशल आधारित तथा कोर सेक्टर के डाउन स्ट्रीम उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। निवेशकों को ऑन लाइन, स्वप्रमाण, डीम्ड एप्रूवल, स्टेट पीएमजी पोर्टल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। पीपीपी मॉडल में दो रेल कॉरीडोर परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। दल्लीराजहरा-रावघाट परियोजना में 17 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण हो चुका है। सूरत-पाराद्वीप गैस पाइप लाइन परियोजना का लाभ छत्तीसगढ़वासियों को दिलाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में दो फूड पार्क की स्थापना प्रगति पर है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की इकाई की स्थापना भी प्रक्रियाधीन है। राज्य में व्यवसाय को सरल, सुगम बनाने एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कर प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। करों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, ताकि कर दाता स्वयं आगे बढ़कर करों का भुगतान करें।

34. मेरी सरकार ने हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के माध्यम से आजीविका चलाने वाले परिवारों को चिन्हांकित कर उन्हें प्रशिक्षण, विपणन तथा आर्थिक सुविधाएं दी है। इस क्षेत्र में परंपरा के साथ नवीनता के समन्वय से रोजगार के अवसरों को दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है। 'शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना' के कारण एक वर्ष में हाथकरघा वस्त्रों की आपूर्ति 87 करोड़ रूपए तक पहुंची थी, अब 95 करोड़ रूपए का नया कीर्तिमान संभावित है। बुनकर सहकारी समितियों का कारोबार बढ़ा है तथा

बुनकरों का पारिश्रमिक बढ़ाने से उन्हें 21 करोड़ रूपए की आय हुई है। मेरी सरकार हाथकरघा वस्त्र, रेशम, माटी शिल्प, बेलमेटल शिल्प जैसे कलात्मक कार्यों को ज्यादा लाभदायक बना रही है।

35. सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और उस पर आम जनता का विश्वास कायम रखना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य में सुलभ न्याय के लिए 28 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। छह नए जिलों में सिविल जिला न्यायालय, सरायपाली में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, दंतेवाड़ा में नक्सली प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्यवाही हेतु 21 फास्टट्रेक कोर्ट तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों की सुनवाई हेतु पांच विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार ने जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए परम्परागत मीडिया के साथ अत्याधुनिक साधनों का उपयोग भी सुनिश्चित किया है। सोशल मीडिया पर बल दिया जा रहा है। 'छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क मोबाइल एप' युवाओं के लिए काफी उपयोगी तथा लोकप्रिय सिद्ध हो रहा है। राज्य में प्रथम बार आयोजित 'रायपुर साहित्य महोत्सव' को देश के सर्वप्रथम 'हिंदी साहित्य महोत्सव' का गौरव मिला है।

36. मेरी सरकार प्रदेशवासियों की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था कायम रखने के प्रति संजीदगी से प्रयासरत है। पुलिस बल की संख्या, सुविधा एवं दक्षता बढ़ाकर इसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। महिलाओं के लिए टोल-फ्री नम्बर 1091 शुरू किया गया है। चार जिलों में महिला थानों की स्थापना तथा सभी थानों में 'महिला डेस्क' बनाई गई है। प्रदेश के चहुंमुखी विकास में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में सुरक्षाबलों की अहम भूमिका रही है। नई रणनीति और नई ऊर्जा से नक्सलवादी तत्वों का मुकाबला किया जा रहा है। नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण में निरंतर वृद्धि एक सुखद संकेत है।

37. छत्तीसगढ़ ने आप सबके सहयोग से प्रगति के जिन शिखरों को स्पर्श किया है, उसके बहुत आगे जाने की संभावनाएं विद्यमान हैं। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान से यह विधानसभा विकास की नई दिशा और गति निर्धारित करने में सफल होगी ताकि राज्य के जन-जन को विकास, समृद्धि और खुशहाली में भागीदार बनाया जा सके।

जय हिंद

जय छत्तीसगढ़